



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 713]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 30, 1989/कार्तिक 8, 1911

No. 713]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 30, 1989/KARTIKA 8, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर 1989

अधिसूचनाएं

का.आ. 878(अ) — केन्द्रीय सरकार, बैंक की विनियमन अधि-
नियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (7)
के अनुसरण में युन इटेड इंडियन बैंक लि., कलकत्ता के उलाहबद
बैंक के वध समायोजन की स्कीम के संबंध में, जो उक्त उपधारा के
अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गयी है 31 अक्टूबर, 1989
को प्रहित व रोख के रूप में विनिर्दिष्ट करनी है।

[संख्य. 17/2/89-बी.ओ. III(i)]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 30th October, 1989

S.O. 878(E).—In pursuance of sub-section (7) of section
45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the
Central Government hereby specifies the 31st October, 1989
as the prescribed date in relation to the scheme for the amal-
gamation of the United Industrial Bank Limited, Calcutta
with Allahabad Bank, which has been sanctioned by the
Central Government under the provisions of the said sub-
section.

[No. 17/2/89 B.O. III(i)]

का.आ. 879(अ) — केन्द्रीय सरकार ने बैंक की विनियमन अधि-
नियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (1)
के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए आवेदन पर, उक्त धारा
की उपधारा (2) के अधीन युन इटेड इंडियन बैंक लिमिटेड, कलकत्ता
के संबंध में उक्त धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना प्रदान
किया है;

और भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलाहाबाद बैंक के साथ युनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता के सम्मेलन की स्वीकृति तैयार की है;

और रिजर्व बैंक ने उक्त धारा को उपधारा (6) के उपबन्धों के अनुसार उक्त स्कीम का प्राकृतिक संबंधित बैंकों को भेजने के पश्चात् और उक्त स्कीम की बाबत प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् वह स्कीम उपन्तर्गत की है और उसे मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजा है।

अब अतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसमें अनेक वर्णित निबंधनों और शर्तों के अधीन रखते हुए इस स्कीम को मंजूरी दे दी है।

(1) युनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता अन्तरक बैंक होगा और इलाहाबाद बैंक अन्तरिती बैंक होगा।

(2) ऐसी तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम, की धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन इस प्रयोजन के लिए विनियम करे (जिसे इसमें इसके पश्चात् विहित तारीख कहा गया है) अन्तरक बैंक के सभी अधिकार, शक्तियां मांग, बाब, हित, प्राधिकार, विशेषाधिकार, साधन, धस्तियां और जंगम और स्वरूप सम्पत्ति जिसके अन्तर्गत भू-धूमि के सभी आपातनों या पट्टों या करारों द्वारा प्राप्त और उनमें प्रत्यक्ष, भाटकों और अन्य धनराशियों और प्रसंगविदाओं के अधीन परिसर जिसके अधीन वे धारित हैं, सभी कार्यलय, फर्निचर, विद्युत् उपकरण, संयंत्र, यंत्र और साधन, बही, कागज-पत्र लेखन सामग्री स्टॉक, अन्य स्टॉक और सामान, सभी स्टॉक विनिधान शेयर और प्रतिभूतियां, हथ में और भविष्य में प्राप्त सभी ढुंढियों सभी हथ की और लेखा की रोकड़ या बैंकों के पास निक्षेप लेखा (जिसके अन्तर्गत मांग पर या संक्षिप्त सूचना पर धन भी है) बुलियन, सभी बची ऋण, बंधक, ऋण और प्रतिभूतियों के फायदे सहित अन्य ऋण या उसकी कोई प्रत्यभूति अन्तरक बैंक के कारबार के संबंध में सभी अन्य, यदि कोई हों, सम्पत्ति अधिकार और सभी प्रत्यभूतियों के अस्तित्व संबंधी फायदे, इस स्कीम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तरिती बैंक को अन्तरित हो जाएंगे और उसकी सम्पत्ति और धस्तियां बन जाएंगे और विहित तारीख से ही अन्तरक बैंक के सभी दायित्व कर्तव्य और फायदे इसमें इसके पश्चात् उपबंधित विस्तार तक और रीति में अन्तरिती बैंक के दायित्व कर्तव्य और बाध्यताएं होंगे और बन आयेंगे।

पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सभी संविदाएं विलेख, बंधपत्र, करार, मुकदमों में, विधि प्रतिनिधित्व की मंजूरीयों और किसी भी प्रकृति की अन्य लिखतें जो विहित तारीख के ठीक पहले अस्तित्वशील या प्रभावशील हों, अन्तरिती बैंक के विरुद्ध या उसके पक्ष में इसमें उपबंधित विस्तार तक और रीति में प्रभावशाली होंगी और जैसे ही कार्यान्वित की जा सकेंगी सभी अन्तरक बैंक के स्थान पर अन्तरिती बैंक उसमें पक्षकार रहा हो, माना ये अन्तरिती बैंक के पक्ष में जारी की गयी हों।

यदि विहित तारीख को अन्तरक बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद, अपील या किसी भी प्रकृति की कोई अन्य विधिक कार्यवाही लंबित है तो उसका उपसमन नहीं होगा वह बंद नहीं होगी या उस पर किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्तु वह इस स्कीम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तरिती बैंक के द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेगी और प्रवर्तित की जा सकेगी।

यदि भारत से बाहर के किसी देश की विधि के अनुसार इस स्कीम के उपबन्ध उस देश में स्थित किसी ऐसी अस्तित्व या दायित्व को जो अन्तरक बैंक के उपक्रम के भाग हैं, अन्तरिती बैंक को अन्तरित या उसमें निहित करने का प्रभाव स्वयं नहीं रखने तो ऐसी अस्तित्व या दायित्व के संबंध में अन्तरक बैंक का कार्य-कलाप विहित तारीख से अन्तरिती बैंक के तत्काल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी में स्थित हो जाएगा और वह कार्यपालक अधिकारी ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा तथा ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा, जो प्रभावी रूप से इसके कार्य-कलाप के परिणामों के प्रयोजन के लिए अन्तरक बैंक द्वारा प्रयुक्त की जा सकती या की जा सकती हैं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसा अंतरण और निहित करने के प्रयोजन के लिए ऐसी सभी कार्यवाहियां करेगा, जो भारत के बाहर किसी ऐसे देश की विधियों द्वारा अपेक्षित हों और उस संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, या तो स्वयं या अपने द्वारा निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा अन्तरक बैंक की अस्तित्व बतूत कर सकेगा या उसके दायित्व का निर्वहन करेगा और उसके शुद्ध आगमों का अन्तरिती बैंक को अन्तरित कर देगा।

3. अन्तरक बैंक की बहियां बंद की जाएंगी और उनकी तुलना की जाएगी और तुलन-पत्र प्रथमतः 10 जून, 1989 को कारोबार की समाप्ति पर तैयार किया जाएगा और तुलन-पत्र चार्टर्ड लेखाकार तथा चार्टर्ड लेखा करने की किसी ऐसी फर्म द्वारा जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित या नामनिर्दिष्ट की गयी हो संपरीक्षित और प्रमाणित करण जायेगी।

पूर्वगामी पैरा के उपबन्धों के अनुसार तैयार की गयी अन्तरक बैंक के तुलन-पत्र को प्रत्येक प्रति अन्तरक बैंक द्वारा प्राप्त हो जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र कम्पनी रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी और तत्पश्चात् अन्तरक बैंक से तुलन-पत्र या लाभ और हानि लेखा तैयार करने या उसे सबसों के समक्ष प्रस्तुत करने या उसकी प्रतियां कम्पनी रजिस्ट्रार के पास फाइल करने की या तुलन-पत्र और लेखों पर विचार करने के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159 के उपबन्धों के अनुपालन करने के लिए व्यक्ति संधारण अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और तत्पश्चात् अन्तरक बैंक के निवेशक बोर्ड के लिए उस अधिनियम की धारा 245 की अपेक्षानुसार अधिवेशन करना आवश्यक नहीं होगा।

4. 1—अन्तरिती बैंक, अन्तरक बैंक के परामर्श से निम्नलिखित उपबन्धों के अनुसार अन्तरक बैंक की सम्पत्तियों और धस्तियों का मूल्यांकन करेगा और दायित्वों की संगणना करेगा अर्थात्:—

(क) सरकारी प्रतिभूतियों से भिन्न विनिधानों का मूल्यांकन विहित तारीख की ठीक पूर्ववर्ती तारीख को विद्यमान बाजार बरों पर किया जाएगा।

(ख) (i) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के प्रयोजन के लिए जारी की गयी अधिसूचना में अधिकृत सिद्धांतों के अनुसार विहित रीति रीति में ठीक पूर्ववर्ती तारीख को यथा विद्यमान रूप में किया जाएगा।

(ii) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों जैसे डाकघर-प्रमाण पत्र ट्रेजरी बचत निक्षेप प्रमाण-पत्र और केन्द्रीय सरकार की लघु बचत योजना के अधीन जारी की गयी कोई अन्य प्रतिभूतियां या प्रमाण नहीं पक्षों की मूल्यांकन उनके अंकित मूल्य के आधार पर या उक्त तारीख को

नकद प्राप्त मूल्य के आधार पर, इन दोनों में से जो भी उच्चतर हो, किया जायेगा।

(iii) जहाँ किसी सरकारी प्रतिभूति जैसे जमीन की उत्पन्न, बंधनपत्र या अन्य सामान्य प्रतिभूति जिसकी बाबत मूल्य किस्तों में देय है, का बाजार मूल्य अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है या किसी कारणवश यह माना जाता है कि यह उसका उचित मूल्य प्रदर्शित नहीं करता है या वह अन्यथा उचित नहीं है, तो प्रतिभूति का मूल्यांकन उतनी रकम पर किया जायेगा जो संदेह किए जाने वाले बकाया मूल और उसकी ब्याज की किस्तों को उस कालावधि को जिसके दौरान ऐसे किस्तों है, सरकार द्वारा जारी की गयी किसी प्रतिभूति के मूल्य को जिससे प्रतिभूति का संबंध है और जिसकी वैसी ही या लगभग वैसी ही परिपक्वता है या वह सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त समझा जाता है।

(ग) जहाँ किसी प्रतिभूति, शेयर, डिबेंचर, बंधनपत्र या अन्य विनिधान का बाजार मूल्य उसके असामान्य बातों से प्रभावित हो जाने के कारण युक्तियुक्त नहीं माना जाता है, वहाँ विनिधान का मूल्यांकन किसी युक्तियुक्त कालावधि के दौरान उसके औसत बाजार मूल्य के आधार पर किया जायेगा।

(घ) जहाँ किसी प्रतिभूति, शेयर या डिबेंचर या अन्य विनिधान का बाजार मूल्य अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, वहाँ जारी करने वाले समुधान की वित्तीय स्थिति, पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के दौरान उसके द्वारा सदत्त लाभों और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, केवल ऐसे मूल्य को यदि कोई है, हिसाब में लिया जायेगा जो युक्तियुक्त मूल्य माना जायेगा।

(ङ) दावों की पूर्णता के लिए अर्जित परिसरों और अन्य सभी जमा सम्पत्तियों और किन्हीं अस्तित्वों का मूल्यांकन उनके बाजार मूल्य पर किया जायेगा।

(च) फर्नीचर और पक्वशर, स्टोक की लेखन सामग्री और अन्य अस्तित्वों, यदि कोई हों, का मूल्यांकन प्रति वही अधिकारित मूल्य के आधार पर या बमूनी योग्य मूल्य के आधार पर, जो भी युक्तियुक्त समझा जाए, किया जायेगा।

(छ) अग्रिमों, जिनके अन्तर्गत कय की गयी और मालिकाएँ पर गृहगत की गयी हुई हैं, दोनों और विधि अस्तित्वों की समीक्षा अंतरिम बैंक द्वारा की जायेगी और विधि प्रतिभूतियों जिनके अन्तर्गत उसके आवश्यक के रूप में धारित प्रतिभूतियाँ भी हैं, अंतरिम बैंक द्वारा परीक्षित और मूल्यांकित हो जाएंगी। तत्पश्चात् अग्रिम जिनके अन्तर्गत उनके भाग भी हैं जो श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाएंगे, अर्थात् "बे अग्रिम जित्ने अच्छा और आसानी से बमूनी योग्य माना गया है/ और "बे अग्रिम, जित्ने आसानी से बमूनी योग्य" माना नहीं गया है" और/या जिनकी बमूनी इवत या शक्यता है।

(i) इस स्कीम प्रयोजनों के लिए दायित्वों के अंतर्गत ऐसी सभी समाश्रित दायित्व भी हैं जिनके लिए अंतरिम बैंक से विहित तारीख को या उसके पश्चात् अपने स्वयं के स्रोतों में उचित रूप में पूँजी लाने की आशा या अपेक्षा की जा सकेगी।

(ii) जहाँ किसी अस्तित्व का मूल्यांकन विहित तारीख को आधारित नहीं किया जा सकता है वहाँ वह भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से भागतः या पूर्णतः किसी पश्चात्पूर्व तारीख को बमूनी योग्य अस्तित्व के रूप में जाना जायेगा। किसी अस्तित्व के मूल्यांकन और/या किसी अग्रिम के वर्गीकरण और/या किसी दायित्व के अवधारण की बाबत अंतरिम बैंक और अन्तरक बैंक के बीच कोई सहमति है, रिजर्व बैंक को निर्देशित किया जाएगा जिसका राय अंतिम होगी परंतु जब तक ऐसी राय प्राप्त नहीं हो जाते तब तक अंतरिम बैंक द्वारा मर्गों या उस भाग का मूल्यांकन इस स्कीम के प्रयोजन के लिए अनन्तित रूप से अयनाया जायेगा।

ऐसा करना आवश्यक होने की वशा में रिजर्व बैंक के लिए ऐसा के बीच कोई असहमति है, तो "यह मासधा भारतीय किसी भद्र के मूल्यांकन या दायित्व की ऐसी किसी भद्र के अवधारण के संबंध में समुचित समझे, और ऐसी राय अभिप्राप्त करने का अन्य अन्तरक बैंक की अस्तित्वों में से पूर्ण रूप से देय होगा।

पूर्वगामी उपबन्धों के अनुसार अस्तित्वों का मूल्यांकन और दायित्वों का अवधारण दोनों बैंकों और उसके सदस्यों और लेनदारों पर बाबदकर होगा।

5. अन्तरक बैंक की संपत्ति और अस्तित्वों के अंतरिम बैंक को अन्तरण होने के प्रतिफल स्वरूप अंतरिम बैंक इसे और निम्नलिखित खण्डों में वर्णित विस्तार तक अन्तरक बैंक के दायित्वों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:

(क) विहित तारीख तक कर्मचारीवृत्त प्रतिभूति निक्षेपों सहित उस पर प्रीम्यूट व्याज यदि कोई है, के साथ उस बैंक के पास अन्तरक बैंक के किसी कर्मचारी द्वारा जमा की गयी कोई धनराशि और विहित तारीख को सभी अन्य बाह्य दायित्व, जिसके अन्तर्गत निक्षेप नहीं हैं, सदत्त किए जाएंगे या उनकी पूर्ण व्यवस्था की जाएगी।

स्पष्टीकरण:— इस पैरा के प्रयोजन के लिए विहित तारीख तक निक्षेप पर देय व्याज संवद्ध निक्षेप का भाग माना जायेगा।

(ख) प्रत्येक बचत बैंक खाते या बालू खाते या किसी अन्य निक्षेप की बाबत जिनके अन्तर्गत सावधि निक्षेप, नकद प्रमाण-पत्र, मासिक निक्षेप, मांग या संक्षिप्त सूचना पर देय निक्षेप या अन्तरक बैंक के पास कोई अन्य निक्षेप जहाँ वे किसी भी नाम से जाने जाते हों और कोई अन्य खाते जो खण्ड (क) के अन्तर्गत आते हैं जिसके अन्तर्गत इस स्कीम के अग्रिम देय सीमा तक व्याज भी है। अंतरिम बैंक विहित तारीख को संबंधित धारक/कों के नाम में एक समान और वैसा ही खाता खोलेगा जिसमें विहित तारीख को इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए पैरा (4) में निर्दिष्ट तथा मूल्यांकित अस्तित्वों में से प्रत्येक खाते के संबंध में उपलब्ध आनुपातिक शेयर मूल्य के रूप में जमा करेगा और इस प्रकार मूल्यांकित उक्त अस्तित्वों में से वे अग्रिम जो आसानी से बमूल योग्य नहीं माने गए हैं, या इवत हैं या जिनकी बमूनी शक्यता है, कोई अन्य अस्तित्वों या अस्तित्व के भाग जो विहित तारीख को मूल्यांकित नहीं हैं और अन्य रकम जो ऊपर खण्ड (क) में वर्णित संदाय या उपबन्धों के लिए अपेक्षित हैं, अपेक्षित किए जाएंगे और इस प्रकार मूल्यांकित उक्त अस्तित्वों में अन्तरक बैंक को जारी किए गए तारीख 10 जून, 1989

के अधिस्थगत आदेश के पैरा 2 के खण्ड (क) (1) के आधार पर किए गए संदायों की संकलित रकम जोड़ेगा।

परन्तु 10 जून 1989 को कारोबार की समाप्ति का या उसके पश्चात् और विहित तारीख के पूर्व किसी विशेष खाते से किए गए किसी संदाय की संगणना इस उप पैरा के अधीन जमा की जाने वाली रकम के मदों की जाएगी और तदनुसार जमा की जानेवाली रकम आनुपातिक शेयर होंगी जिसमें ऐसे संदाय की रकम कम कर दी जायेगी।

परन्तु यह और कि जहाँ अंतरिती बैंक को किसी विशेष खाते में की गयी प्रतिष्ठियों के सही होने के बारे में कोई युक्तियुक्त संदेह है तो वह रिजर्व बैंक के अनुमोदन से ऊपर खण्ड (ग) के आधार पर उस लेख में किए जाने वाले जमा धनराशि को प्रतिधारित कर सकेगा। जब तक कि अंतरिती बैंक ऐसे खाते में सही अधिगण अभिलिखित नहीं कर जाता है।

स्पष्टीकरण :

“आनुपातिक” पद में, जहाँ तक वह इस पैरा में आता है ऐसी संबंधित रकमों के अनुपात में अभिप्रेत है जो 10 जून 1989 को कारोबार की समाप्ति पर बकाया देय है (विहित तारीख के ठीक पूर्ववर्ती तारीख तक देय व्याज सहित) और जहाँ तक वह इस स्कीम में अत्यंत आता है, से ऐसी संबंधित रकमों के अनुपात में अभिप्रेत है जो संदाय या वितरण के समय बकाया देय है।

(ग) ऊपर खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट जमा धनराशि दिए जाने के पश्चात् अंतरिती बैंक संभवतः कम से कम विलम्ब से किन्तु विहित तारीख से तीन मास तक निवेश बीमा और प्रत्यय गारंटी नियम अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित निवेश बीमा और प्रत्यय गारंटी नियम को (जिसे इसमें इसके पश्चात् निगम कहा गया है) एक सूची देगा, जिसमें सभी प्रकार के उस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, और तत्पश्चात् अब भी उस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) में निश्चित रकम नियम से प्राप्त हों, अंतरिती बैंक उस तारीख या तारीखों से जिसकी रकम प्राप्त होती है, तीन दिन के अन्दर उस खाते में वेय धनराशि के विस्तार तक, उस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के अनुसार ऊपर खण्ड (ख) में निश्चित प्रत्येक खातों में जमा करेगा। परन्तु :—

(i) यदि खण्ड (ख) में निश्चित कोई खाता बन्द कर दिया गया है या वह ऐसे समय पर जब उस खाते में जमा के लिए रकम निगम से प्राप्त होती है, परिपक्व हो गया है तो उक्त रकम के हकदार व्यक्ति को संदाय अंतरिती बैंक द्वारा नकद रूप से किया जायेगा।

(ii) यदि खण्ड (ख) में निश्चित किसी रकम के हकदार व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है या उसका आसानी से पता नहीं चल पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को देय रकम के लिए उपर्युक्त स्वयं निगम की बहियों में किया जाएगा और उसका पूषक रूप से लेखा दिया जाएगा तथा अंतरिती बैंक को किसी रकम का संदाय करना निगम के लिए आवश्यक नहीं होगा जब तक कि रकम का हकदार व्यक्ति मिल नहीं जाता है या उसका पता नहीं मिल जाता है और निगम के अंतरिती बैंक के माध्यम से उस व्यक्ति की बाबत संदाय करने का विनिश्चय नहीं कर लिया है।

(घ) विहित तारीख को अंतरिती बैंक की समाप्त पूंजी सम्पूर्ण रकम और आरक्षितों की जूबन और गंवास्पद श्रृण के लिए उपर्युक्त के रूप में माना जाएगा और अंतरक बैंक की अधिस्थगत आदेशों में अवश्यत और अंतरक बैंक के सदस्यों के अधिस्थगत अंतरिती बैंक में ऐसे होंगे जो नीचे पैरा (6) में उप-बंधित हैं।

(6) निम्नलिखित की बाबत :—

(क) पूर्ववर्ती पैरा के खण्ड (ख) में वर्णित प्रत्येक लेख, की बाबत उन खण्ड और खण्ड (ग) के आधार पर किसी लेख, यदि कोई है, में जमा न किया गया अतिरिक्त और

(ख) अंतरक बैंक में प्रत्येक शेयर की बाबत जितनी रकम को विहित तारीख से ठीक पूर्व प्रत्येक शेयर धारक के द्वारा या उसकी ओर से शेयर पूंजी के भदे समाप्त रूप में माना गया था या नीचे (1) के अनुसरण में अंतरिती बैंक द्वारा की गयी मांग के भदे रकम संयत की गयी थी, संग्रहण लेख के रूप में माना जाएगा और उसे अंतरिती बैंक की बहियों में इस प्रकार दर्ज किया जाएगा और लेखा के विरुद्ध संदाय निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात् :—

(1) (क) अंतरिती बैंक प्रथमतः ऐसे व्यक्ति से जो विहित तारीख को अंतरक बैंक में अधिस्थगत शेयर धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत था (या जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किए जाने के हकदार होता है) ऐसी तारीख या तारीखों से तीन मास के अन्दर जो विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसे शेयर या शेयरों और बकाया मांगों, यदि कोई हों, की बाबत उसके द्वारा अवसंत रह रही अनाहत रकम का संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा और तत्पश्चात् यदि यह आवश्यक पाया जाता है तो वह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से जो विहित तारीख की अंतरक बैंक के साधारण शेयर धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत था (या जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होता है) ऐसी तारीख या तारीख से जो विनिर्दिष्ट की जाए, तीन मास अन्दर ऐसे शेयर या शेयरों या बकाया मांगों, यदि कोई हों, की बाबत उसके द्वारा अवसंत रह रही अनाहत रकम का संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(ख) अंतरक बैंक प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत की कालावधि के लिए छः प्रतिशत वार्षिक व्याज सहित खण्ड (क) के अधीन वेय रकम के संदाय की मांग और उसे प्रवर्तित करने के लिए सभी उपलब्ध कदम उठायेगा।

(2) अंतरिती बैंक अधिमों, त्रय या मितिकटा किए गए भूगस्तन, बुझियों, बर्हा त्रणों और विविध त्रणों तथा अन्य आस्तियों की बाबत जो “ऐसे अधिमों के रूप में जो आसानी से बसूली योग्य नहीं है और या बसूली के लिए जूबन या गंवास्पद” है, के रूप में वर्तित किया गया है या जो ऊपर पैरा 4 के आधार पर विहित तारीख के पश्चात् पूर्णतः या भागतः बसूली योग्य है या हो सकते हैं के संबंध में मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, संदाय की मांग और उसे प्रवर्तित करने के लिए सभी उपलब्ध कार्यवाही करेगा परन्तु यह और कि किसी त्रण या आस्तिक की रकम 50,000 रुपये से अधिक है, तो अंतरिती बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बिना :

(क) त्रण या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई सम्झौता या ठहराव नहीं करेगा या किसी ऐसे त्रण या आस्तिक को बंदूट खाते में नहीं डालेगा।

(ख) उसे अंतर्गत किसी प्रतिभूतियों का या उसके द्वारा की गयी किसी धर्मिता का विकल्प या अन्यथा ध्वनन नहीं करेगा।

(3) इसके अंतर्गत, अंतर्गती बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45ज के साथ और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 543 के साथ भी पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45ड के अधीन अंतर्गती बैंक के निर्माण प्रवर्तक, निवेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा नुकसानों के रूप में अधिनियमित की गयी रकम यदि कोई हो, की माँग करने और उनका संदाय करवाने के लिए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मनी उपलब्ध कार्यवाहियाँ करेगा,

(4) अंतर्गती बैंक, उपर्युक्त खण्ड (1)(2) और (3) में उल्लिखित मर्दों के कारण अपने द्वारा की गयी वसूलियों में से किसी समाश्रित दायित्व की बाबत, और रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से किसी ऐसे दायित्व, चाहे वह समाश्रित हो या अस्थायिक, की बाबत, जिसे उपर्युक्त पैरा (4) निबंधनों के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया था और जो विहित तरीख को या उसके पश्चात् उद्भूत हुआ है या जिसका पता चला है, संदाय कर सकेगा या उस मीमा तक, जो पैरा 45क के अधीन उसके लिए किया गया उपबन्ध अपर्याप्त हो, उपबन्ध कर सकेगा।

(5) अंतर्गती बैंक, उपर्युक्त खण्ड (1)(2) और (3) में उल्लिखित मर्दों के कारण अपने द्वारा की गयी वसूलियों में से, उस प्रयोजन के लिए उपगत धन की और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से ऐसे अन्य धन की जो उचित समझा जाए, उनमें से कटौती करने और उपर्युक्त खण्ड (4) के निबंधनों के अनुसार उसमें से रकम विनियोजित करने के पश्चात् या ऐसे अधिशेष, यदि कोई हो, में से, जो ऐसे दायित्वों की मीमा अंतिम रूप से अभिनिश्चित की जाने के पश्चात् इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए यथा संगणित समाश्रित दायित्वों की बाबत उपबन्ध में से उपलब्ध हो।

(क) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन अंतर्गती बैंक द्वारा निगम से प्राप्त रकम और निगम द्वारा उपबन्धित रकम, यदि कोई हो, का संदाय करेगा, और

(ख) ऐसे निक्षेपकर्ताओं के मामले में, जिनकी बाबत अंतर्गती बैंक द्वारा कोई रकम निगम से प्राप्त नहीं की गयी है, संग्रहण खाते की बाबत शोध्य रकमों का, और ऐसे निक्षेपकर्ताओं के मामले में जिनकी बाबत अंतर्गती बैंक द्वारा कोई रकम निगम से प्राप्त की गयी है या निगम द्वारा उपबन्धित की गयी है, निगम द्वारा किए गए या उपबन्धित संदाय की बाबत निगम को उक्त खाते में शोध्य रकमों को उपर्युक्त उपखण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार पहले संदाय किए जाने के पश्चात् उनके संग्रहण खाते में उन्हें शोध्य अधिशेष यदि कोई हो, का संदाय करेगा।

परन्तु यह कि निगम को शोध्य रकम, यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो, अंतर्गती बैंक की महियों में उपबन्धित की जाएगी तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम साधारण विनियम, 1961 के विनियम 10 खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट रीति से निगम को संदाय की जाएगी। परन्तु यह और कि अंतर्गती बैंक, उपर्युक्त खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट संदाय उस वृत्ति में करेगा:—

(1) यदि पैरा (5) के खण्ड (ख) में उल्लिखित तत्समान या समरूप खाते को बन्द नहीं किया गया है या वह उस खाते में प्रत्यय द्वारा भुगतान के लिए परिपक्व नहीं हुआ है, और

(2) यदि उक्त खाते को बन्द कर दिया गया है या वह नफ़ा भुगतान के लिए परिपक्व हो गया है।

(6) उपर्युक्त खण्ड (5) के उपखण्ड (क) के निबंधनों के अनुसार निगम को शोध्य रकमों, और उस खण्ड के उपखण्ड (ख) के निबंधनों के अनुसार निक्षेपकर्ताओं के संग्रहण खाते में शोध्य रकमों की श्रेणी आपन में समान होंगी और यदि उनका संदाय पूर्णतः नहीं किया जा सकता हो उनमें समान अनुपात में कमी होगी।

(7) इसके पिर, के खण्ड (5) में निर्दिष्ट संदाय के लिए जाने या पूर्णतः उपबन्धित किए जाने के पश्चात् अंतर्गती बैंक खण्ड (5) में निर्दिष्ट रकमों के उस अधिशेष, जो उसके पास उपलब्ध हो, में से, अंतरक बैंक के भूतपूर्व शेष-धारकों के खाते में शोध्य रकम, यदि कोई हो, हेतु ऐसी रीति से और उस मीमा तक, जो नीचे विनिर्दिष्ट है, अनुपातिक संदाय करेगा:—

(क) प्रथमतः सब खाते के लिए पूर्णतः संदाय किए जाने तक अंतरक बैंक के भूतपूर्व अधिमान शेष-धारकों के खाते में शोध्य रकम, यदि कोई हो,

(ख) द्वितीयतः सब खाते के लिए पूर्णतः संदाय किए जाने तक अंतरक बैंक के भूतपूर्व सामान्य शेष-धारकों के खाते में शोध्य रकम, यदि कोई हो और उसके पश्चात्,

(ग) तृतीयतः सब खाते के लिए पूर्णतः संदाय किए जाने तक अंतरक बैंक के भूतपूर्व अस्थायित शेष-धारकों के खाते में शोध्य रकम, यदि कोई हो,

(घ) उपर्युक्त उपखण्ड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित सब रकम को पूर्णतः संदाय करने के पश्चात् अंतर्गती बैंक के पास बची बचे अधिशेष का, अंतरक बैंक भूतपूर्व सामान्य शेष-धारकों के बीच अनुपातिक वितरण किया जाएगा।

परन्तु यह कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि उपर्युक्त किसी उप-खण्ड में उल्लिखित खाते के लिए कोई रकम शोध्य है या नहीं हो तो उसे भारतीय रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(8) इस पैरा में निर्दिष्ट संग्रहण खाते में शोध्य रकम के बारे में केवल अंतर्गती बैंक का दायित्व उस मीमा, तक समझा जाएगा जो इस स्कीम में उपबन्धित है।

(9) विहित तरीख या ऐसी पूर्वतर अवधि से जो केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करे, बारह वर्ष के अवसान पर, इस पैरा, के खण्ड (2) में निर्दिष्ट किसी ऐसी मद का, जो उस तरीख तक वसूल नहीं, की जा सकी हो, मूल्यांकन अंतर्गती बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से किया जाएगा और अंतर्गती बैंक, उक्त मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, अवधारित कोई रकम इस पैरा के खंड (4) में निर्दिष्ट दायित्वों की पूर्ति के लिए आवश्यक किसी ऐसी राशि की जो उपर्युक्त खण्ड (5), (6) और (7) में उपबन्धित क्रम और रीति से उस तरीख तक चुकायी जाने से रह गयी हो, पहले उनमें से कटौती करके वितरित करेगा।

(10) अंतर्गती बैंक, पूर्ववर्ती खण्ड (1), (2) और (3) में उल्लिखित मर्दों के कारण वसूल किए गए ऐसे धन को, जिनकी गुरता संदाय के लिए उसके द्वारा अपेक्षा किए जाने की संभावना नहीं है, अपने पास या किसी अन्य बैंक या बैंकों के पास ध्याज वाले निक्षेपों में ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के लिए, जो मामले के तथ्यों

और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त हो या जैसा भारतीय रिजर्व बैंक निदेश दे, विनिर्दिष्ट करेगा। प्रोद्भूत व्यय को खण्ड (4), (5), (6) और (7) में निर्दिष्ट दायित्वों की पूर्ति के लिए उनमें उपदर्शित रीति में उपयोजित किया जाएगा।

7. किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा में किसी प्रसिद्ध बात के होते हुए भी, पैरा (5) के निबन्धनों के अनुसार अंतरिती बैंक के पास खोले गए नए खातों की बाबत व्याज का संदाय किया जाएगा और उसके केवल उन या अपने उत्तरवर्ती पराधी के उपबन्धों के अनुसार ऐसी दरों पर, जो अंतरिती बैंक अनुज्ञात करे जमा किया जाएगा।

8. कोई भी निक्षेपकर्ता या अंतरक बैंक का अन्य लेनदार, उसके प्रति अंतरक बैंक के किसी दायित्व की बाबत अंतरक बैंक या अंतरिती बैंक से इस स्कीम द्वारा विहित बीमा के सिवाय, कोई मांग का हकदार नहीं होगा।

9. केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या अंतरिती या अंतरक बैंक के अधिकाधिकारी ऐसी बात के लिए कोई बाध या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी, जो इस स्कीम के अनुसरण में सम्भावपूर्वक की गई हैं या की जाने के लिए आशयित हैं।

10. अंतरक बैंक के सभी कर्मचारी सेवा में बने रहेंगे और यह समझा जाएगा कि उन्हें अंतरिती बैंक द्वारा उसी परिश्रमिक और सेवा के उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया गया है जो 10 जून, 1989 को कारबार बंद होने के ठीक पहले ऐसी कर्मचारियों की लागू थी।

परन्तु यह कि अंतरक बैंक के ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने अंतरक बैंक या अंतरिती बैंक को, उस तारीख के, जिसको यह स्कीम केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किया गया है, ठीक आगामी एक मास के अवसान के पूर्व किसी भी समय अंतरिती बैंक के कर्मचारी न होने के अपने आग्रह के बारे में लिखित सूचना द्वारा सूचित किया है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अधीन ऐसे प्रतिकार, यदि कोई हों, और ऐसे पेशान, उपदान भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति फायदे संदाय के लिये हकदार होंगे, जो 10 जून, 1989 को कारबार के बंद होने के ठीक पहले अंतरक बैंक के प्राधिकरण नियमों के अधीन सामान्य तौर पर अनुज्ञेय हों।

परन्तु यह और कि अंतरक बैंक के ऐसे कर्मचारियों की बाबत, जिनके बारे में यह समझा जाता है कि उन्हें अंतरिती बैंक के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया है, अंतरिती बैंक के बारे में भी यह समझा जाएगा कि उसने अंतरिती बैंक की सेवा में रहने के दौरान उनकी छुट्टी की दशा में इस आधार पर छुट्टी प्रतिकार के संदाय का दायित्व लिया है कि उनकी सेवा निरन्तर बनी रहती है और अंतरिती बैंक में उनके स्थानान्तरण से विच्छिन्न नहीं हुई है।

11. अंतरिती बैंक, उस तारीख से जिसको इस स्कीम को मंजूर किया जाना है, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के अवसान पर, अंतरक बैंक के कर्मचारियों को वही पारिश्रमिक और सेवा के वही निबंधन और शर्तें संदाय या मंजूर करेगा, जो अंतरिती बैंक के तत्कालीन रोक या प्रास्थिति के कर्मचारियों को, अंतरिती बैंक के ऐसे अन्य कर्मचारियों के समान या समतुल्य अंतरक बैंक के उच्चतम कर्मचारियों के पास अर्हताएं और अनुभव के अधीन रहते हुए, लागू हों;

परन्तु यह कि यदि कोई शंका या मतभेद उत्पन्न होता है कि कर्मचारियों में से किसी की अर्हताएं या अनुभव अंतरिती बैंक के तत्कालीन रोक या प्रास्थिति के अन्य कर्मचारियों की अर्हताएं और

अनुभव के समान या समतुल्य है या नहीं या वह अंतरिती बैंक के तत्कालीन रोक में कर्मचारियों का वेतन नियत करने के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धान्तों की प्रक्रिया के संबंध में है, तो शंका या मतभेद को भारतीय रिजर्व बैंक को निविष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

12. यथास्थिति, अंतरक बैंक या अंतरिती बैंक के कर्मचारियों के लिए गठित किसी भविष्य निधि और/या उपदान निधि के न्यासी या प्रशासक, विहित तारीख को या उसके पश्चात् यथासंभव गीघ्र, अंतरिती बैंक के लिए गठित कर्मचारी भविष्य निधि और/या उपदान निधि के न्यासी को, या अथवा, जैसा अंतरिती बैंक निदेश दे, अंतरक बैंक के कर्मचारियों के फायदे के लिए न्यास में धारित सब धन और विनिधान अंतरित कर देगे।

परन्तु यह कि ऐसे पश्चात्कर्ती न्यासी, विनिधानों के मूल्य में किसी कर्मा के लिए, या विहित तारीख या पहले किए गए किसी कार्य, उपेक्षा, या व्यतिक्रम की बाबत दायी नहीं होंगे।

13. अंतरिती बैंक, ऐसे विवरण और जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक को भेजेगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक इस स्कीम के कार्यान्वित करने के संबंध में समय-समय पर अपेक्षा करे।

14. अंतरिती बैंक, अंतरक बैंक के कार्यकलाप का विवरण, ऐसे प्राप्ति में और ऐसे वास्तविक अंतरालों पर, जो भारतीय रिजर्व बैंक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अंतरक बैंक के शेषरधारकों को भेजेगा। ऐसे विवरणों का भेजा जाना तब रोक जायगा जब रिजर्व बैंक ऐसा निदेश दे।

15. किसी ऐसी सूचना या अन्य संसूचना के बारे में, जिसकी अंतरिती बैंक द्वारा दी जाने की अपेक्षा की जाती है, उस दशा में यह समझा जाएगा कि उसे सम्यक रूप से दे दिया गया है, यदि अंतरक बैंक की पुस्तकों में रजिस्ट्रीकृत पते पर, जब तक कि कोई नया पता अंतरिती बैंक की पुस्तकों में रजिस्ट्रीकृत न हो, प्रेषित की सम्बोधित किया गया है और उसे पूर्व-संदन सामान्य डाक से भेज दिया गया है और ऐसी सूचना उसे डाक में डाले जाने के पश्चात्/अवधानों से घटे के अवसान पर तारीख की गयी समझी जाएगी। इसके अतिरिक्त, किसी ऐसी सूचना या संसूचना को, जो सार्वजनिक हित का हो, एक या अधिक दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका परिचालन ऐसे स्थानों पर हो जहाँ बैंक अपने कारबार का सम्बन्धित कर रहा था, विज्ञापित किया जाएगा।

16. यदि इस स्कीम के किसी उपबन्ध या निबंधन करते समय कोई शंका उत्पन्न होती है तो मामले की भारतीय रिजर्व बैंक को निविष्ट किया जाएगा और उसकी राय निश्चायक होगी और अंतरिती बैंक और अंतरक बैंक दोनों पर तथा इस प्रत्येक बैंक के सभी सदस्यों, निक्षेपकर्ताओं और अन्य लेनदारों तथा कर्मचारियों पर भी और किसी ऐसे अन्य व्यक्ति पर, जिसका इन बैंकों में से किसी के सम्बन्ध में कोई अधिकार या दायित्व है, आवद्धकर होगी।

17. यदि इस स्कीम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, अंतरक और अंतरिती बैंकों को या उनमें से किसी को, ऐसे निदेश, जो इस स्कीम से अनगत न हों, जारी कर सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार की भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या उपयुक्त प्रतीत हों।

S.O. 879(E).—Whereas on an application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government has made, under sub-section (2) of the said section 45 an order of moratorium in respect of the United Industrial Bank Ltd., Calcutta, under sub-section (2) of the said section;

And whereas the Reserve Bank of India in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 45 of the said Act has prepared a scheme for the amalgamation of the United Industrial Bank Ltd., Calcutta, with the Allahabad Bank;

And whereas the Reserve Bank of India after having sent the said scheme in draft to the banks concerned in accordance with the provisions of sub-section (6) of the said section and after having considered the suggestions and objections received in regard to the said scheme had modified that scheme and forwarded it to the Central Government for sanction;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 45 of the said Act, the Central Government hereby sanctions the scheme on and subject to the terms and conditions hereinafter mentioned.

(1) The United Industrial Bank Ltd., Calcutta, shall be the transferor bank and the Allahabad Bank shall be the transferee bank.

(2) As from the date which the Central Government may specify for this purpose under sub-section (7) of Section 45 of the said Act (hereinafter referred to as the prescribed date) all rights, powers, claims, demands, interests, authorities, privileges, benefits, assets and properties of the transferor bank, movable and immovable, including premises subject to all incidents of tenure and to the rents and other sums of money and covenants reserved by or contained in the leases or agreements under which they are held, all office furniture, loose equipment, plant apparatus and appliances, books, papers stocks of stationary, other stocks and stores, all investments in stocks, shares and securities, all bills receivable in hand and in transit, all cash in hand and on current or deposit account (including money at call or short notice) with banks bullion, all book debts, mortgage debts and other debts with the benefit of securities, or any guarantee therefor, all other if any, property rights and assets benefit of all guarantees in connection with the business of the transferor bank shall, subject to the other provisions of this scheme, stand transferred to, and become the properties and assets of, the transferee bank; and as from the prescribed date all the liabilities, duties and obligations of the transferor bank shall be and shall become the liabilities, duties and obligations of the transferee bank to the extent and in the matter provided hereinafter.

Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, all contracts, deeds, bonds, agreements, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatever nature subsisting or having effect immediately before the prescribed date shall be effective to the extent and in the manner hereinafter provided against or in favour of the transferee bank and may be acted upon as if instead of the transferor bank the transferee bank had been a party thereto or as if they had been issued in favour of the transferee bank.

If on the prescribed date any suit, appeal or other legal proceedings of whatever nature by or against the transferor bank is pending, the same shall not abate, or be discontinued or be in any way prejudicially affected, but shall subject to the other provisions of this scheme, be prosecuted and enforced by or against the transferee bank.

If according to the laws of any country outside India the provisions of this scheme, by themselves, are not effective to transfer or vest any asset or liability situated in that country which forms part of the undertaking of the transferor bank to or in the transferee bank, the affairs of the transferor bank in relation to such assets or liability shall, on the prescribed date, stand entrusted to the chief executive officer for the time being of the transferee bank and the chief executive

officer may exercise all powers and do all such acts and things as would have been exercised or done by the transferor bank for the purpose of effectively winding up its affairs. The chief executive officer shall take all such steps as may be required by the laws of any such country outside India for the purpose of effecting such transfer or vesting and in connection therewith the chief executive officer may, either himself or through any person authorised by him in this behalf, realise any assets or discharge any liability of the transferor bank and transfer the net proceeds thereof to the transferee bank.

(3) The books of the transferor bank shall be closed and balanced and balance sheets prepared in the first instance as at the close of business on the 10th June, 1989 and thereafter as at the close of business on the date immediately preceding the prescribed date and the balance sheets shall be got audited and certified by a chartered accountant or a firm of chartered accountants approved or nominated by the Reserve Bank of India for the purpose.

A copy each of the balance sheets of the transferor bank prepared in accordance with the provisions of the foregoing paragraph, shall be filed by the transferor bank with the Registrar of Companies as soon as possible after it has been received and thereafter the transferor bank shall not be required to prepare balance sheets or profit and loss accounts, or to lay the same before its members or file copies thereof with the Registrar of Companies or to hold any annual general meeting for the purpose of considering the balance sheet and accounts or for any other purpose or to comply with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 1956, and it shall not thereafter be necessary for the Board of Directors of the transferor bank to meet as required by Section 285 of that Act.

(4) (i) The transferee bank shall, in consultation with the transferor bank, value the property and assets and reckon the liabilities of the transferor bank in accordance with the following provisions, namely,

(a) Investments other than Government Securities shall be valued at the market rates prevailing on the day immediately preceding the prescribed date.

(b) (i) Government Securities shall be valued as on the day immediately preceding the prescribed date in accordance with the principles laid down in the notification issued by Reserve Bank of India for the purpose of Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949.

(ii) The Securities of the Central Government such as Post Office Certificates, Treasury Savings Deposit Certificates and any other securities or certificates issued under the small savings scheme of the Central Government shall be valued at their face value or the encashable value as on the said date, whichever is higher.

(iii) Where the market value of any Government security such as The Zamindari Abolition Bonds or other similar security in respect of which the principal is payable in instalments is not ascertainable or is, for any reason, not considered as reflecting the fair value thereof or as otherwise appropriate, the security shall be valued at such an amount as is considered reasonable having regard to the instalments of principal and interest remaining to be paid, the period during which such instalments are payable, the yield of any security issued by the Government to which the security pertains and having the same or approximately the same maturity, and other relevant factors.

(c) Where the market value of any security, share, debenture, bond or other investment is not considered reasonable by reason of its having been affected by abnormal factors, the investment may be valued on the basis of its average market value over any reasonable period.

- (d) Where the market value or any security, share, debenture, bond or other investment is not ascertainable only such value, if any, shall be taken into account as is considered reasonable, having regard to the financial position of the issuing concern, the dividends paid by it during the preceding five years and other relevant factors.
- (e) Premises and all other immovable properties and any assets acquired in satisfaction of claims shall be valued at their market value.
- (f) Furniture and fixtures, stationery in stock and other assets, if any, shall be valued at the written down value as per books or the realisable value as may be considered reasonable.
- (g) Advances including bills purchased and discounted book debts and sundry assets, will be scrutinised by the transferee bank and the securities, including guarantees, held as cover therefore examined and verified by the transferee bank. Thereafter the advances, including portions thereof, will be classified into two categories namely, "Advances considered good and readily realisable" and "Advances considered not readily realisable and/or bad or doubtful or recovery".

(II) Liabilities for purposes of this scheme shall include all contingent liabilities which the transferee bank may reasonably be expected or required to meet out of its own resources on or after the prescribed date

(III) Where the valuation of any asset cannot be determined on the prescribed date, it may, with the approval of the Reserve Bank of India be treated partly or wholly as an asset realisable at a later date.

In the event of any disagreement between the transferee bank and the transferor bank as regards the valuation of any asset and/or the classification of any advance and/or the determination of any liability, the matter shall be referred to the Reserve Bank of India, whose opinion shall be final, provided that until such an opinion is received, the valuation of the item or portion thereof by the transferee bank shall provisionally be adopted for the purpose of this scheme.

It shall be competent for the Reserve Bank of India in the event of its becoming necessary to do so, to obtain such technical advice as it may consider to be appropriate in connection with the valuation of any such item of asset or determination of any such item of liability, and the cost of obtaining such advice shall be payable in full out of the assets of the transferor bank.

The valuation of the assets and the determination of the liabilities in accordance with the foregoing provisions shall be binding on both the banks and the members and creditors thereof.

(5) In consideration of the transfer of the property and the assets of the transferor bank to the transferee bank, the transferee bank shall discharge the liabilities of the transferor bank to the extent mentioned in this and the following clauses, namely,

(a) Any sums deposited by any employee of the transferor bank with that bank as staff security deposits together with interest, if any accrued thereon upto the prescribed date and all other outside liabilities as on the prescribed date excluding deposits shall be paid or provided for in full.

Explanation.—For the purpose of this paragraph, interest payable on a deposit upto the prescribed date shall be regarded as part of the concerned deposit.

(b) In respect of every savings bank account or current account or any other deposit including a fixed deposit, cash certificate, monthly deposit, deposit payable at call or short notice or any other deposit by whatever name called with the transferor bank and every other account not covered by clause (a), including interest to the extent payable under this

scheme, the transferee bank shall open with itself on the prescribed date a corresponding and similar account in the name of the respective holder(s) thereof crediting thereto the pro rata share available in respect of each of the accounts out of the assets referred to in paragraph (4) as valued for the purposes of this scheme on the prescribed date, after excluding from the said assets as so valued the advances considered not readily realisable or bad or doubtful of recovery, any asset or portion of an asset not valued on the prescribed date and any amount needed for the payment, or provisions mentioned at clause (a) above and after adding to the said assets as so valued the aggregate amount of the payments made in terms of clause (a) (i) of paragraph 2 of the moratorium order dated the 10th June, 1989 issued to the transferor bank :

Provided that any payment made from a deposit account on or after the close of business on 10th June, 1989 and before the prescribed date, shall be reckoned towards the amount to be credited under this sub-paragraph and, accordingly the amount to be credited shall be the pro rata share less the amount of such payment :

Provided further that where the transferee bank entertains a reasonable doubt about the correctness of the entries made in any particular account it may with the approval of the Reserve Bank, withhold the credit to be made in that account in terms of clause (b) above till the transferee bank is able to ascertain the correct balance in such account.

Explanation.—The term 'pro rata' shall, insofar as it occurs in this paragraph, mean in proportion to the respective amounts remaining due as at the close of business on the 10th June, 1989 together with the interest payable upto the date immediately preceding the prescribed date and shall, insofar as it occurs elsewhere in this scheme, mean 'in proportion to the respective amounts remaining due at the time of the payment or distribution'.

(c) After the credits referred to in clause (b) above have been afforded, the transferee bank shall with the least possible delay but in any case not later than three months from the prescribed date, furnish to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation established under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (hereinafter referred to as the Corporation) a list complying in all respects with the requirements of sub-section (1) of Section 18 of that Act and thereafter whenever amounts referred to in sub-section (2) of Section 18 of that Act are received from the Corporation, the transferee bank shall credit each of the accounts referred to in clause (b) above, within seven days from the date or dates on which the amounts are received, to the extent of the sums due to that account in accordance with sub-section (2) of Section 18 of that Act.

Provided that—

(i) If any account referred to in clause (b) above has been closed or has matured for payment at the time when any amount for credit to that account is received from the Corporation, the payment to the person entitled to the said amount shall be made by the transferee bank in cash ;

(ii) In case the person entitled to any amount referred to in clause (b) above cannot be found or is not readily traceable, provision for the amount due to such person shall be made and accounted for separately on the books of the Corporation itself and it shall not be necessary for the Corporation to pay the amounts to the transferee bank unless the person entitled to the amount is found or traced and the Corporation has decided to make the payment in respect of that person through the transferee bank.

(d) On the prescribed date, the entire amount of the paid-up capital and reserves of the transferor bank shall be treated as provision for bad and doubtful debts and depreciation in other assets of the transferor bank and the rights of the members of the transferor bank shall, in relation to the

transferee bank, be as provided for in paragraph (6) below :

(6) In respect of—

(A) every account mentioned in clause (b) of the preceding paragraph, the balance in the account, if any, remaining uncredited in terms of that clause and clause (c) and

(B) every share in the transferor bank, the amount of which was treated as paid-up towards share capital by or on behalf of each shareholder immediately before the prescribed date and/or the amount paid on account of the calls made by the transferee bank in pursuance of clause (i) below,

shall be treated as a collection account and shall be entered as such in the books of the transferee bank and payments against the account shall be made in the following manner, namely :—

(i) (a) the transferee bank shall, in the first instance, call upon every person who on the prescribed date was registered as the holder of a deferred share in the transferor bank (or would have been entitled to be so registered) to pay within three months from such date or dates as may be specified, the uncalled amount remaining unpaid by him in respect of such share or shares and the calls in arrears, if any and thereafter, if it is found to be so necessary, every person who was, as on the prescribed date, registered as the holder of an ordinary share of the transferor bank (or would have been entitled to be so registered) to pay within three months from such date or dates as may be specified, the uncalled amount remaining unpaid by him in respect of such share or shares or the calls in arrears, if any :

(b) the transferee bank shall take all the available steps having regard to the circumstances of each case to demand and enforce the payment of the amounts due under clause (a) above together with interest at six per cent per annum for the period of the default.

(ii) the transferee bank shall in respect of the advances, bills purchased and discounted, book debts and Sundry debts and other assets, which are classified as "Advances considered not readily realisable and/or bad or doubtful of recovery", or which are or may be realisable wholly or partly after the prescribed date in terms of paragraph (4) above, take all available steps having regard to the circumstances of each case to demand and enforce payment, provided, however, that if the amount of a debt or asset exceeds Rs. 50,000, the transferee bank shall not except with the approval of the Reserve Bank of India.

(a) enter into a compromise or arrangement with the debtor or any other person or write off any such debtor asset,

(b) sell or otherwise dispose of any securities transferred to it or any asset taken over by it.

(iii) the transferee bank shall in addition take all available steps having regard to the circumstances of each case to demand and enforce the payment of the amounts, if any, awarded as damages by the High Court against any promoter, director, manager or other officer of the transferor bank under Section 45L of the Banking Regulation Act, 1949, read with Section 45H thereof and also with Section 543 of the Companies Act, 1956 ;

(iv) the transferee bank may, out of the realisations effected by it on account of the items mentioned in clauses (i), (ii) and (iii) above, make payment or provision in respect of any contingent liability to the extent that the provision made therefor under paragraph (5)(a) proves to be inadequate, as also with the prior approval of the Reserve Bank, in respect of any liability whether contingent or absolute which was not assessed in terms of paragraph (4) above and has arisen or been discovered on or after the prescribed date ;

(v) the transferee bank shall out of the realisations effected by it on account of the items mentioned in clauses (i),

(ii) and (iii) above, after deducting therefrom the expenditure incurred for the purpose and, with the approval of the Reserve Bank of India, such other expenses as may be considered reasonable and the amount appropriated therefrom in terms of clause (iv) above, or out of the balance, if any, which may be available from out of the provision in respect of contingent liabilities as reckoned for the purposes of this scheme after the extent of such liabilities has finally been ascertained :

(a) pay to the Corporation the amount received by the transferee bank from the Corporation under sub-section (2) of Section 18 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, and the amount, if any, provided for by the Corporation, and

(b) pay, in the case of depositors in respect of whom no amounts have been received by the transferee bank from the Corporation, the amounts due in respect of the collection accounts, and in the case of depositors in respect of whom any amounts have been received by the transferee bank from the Corporation or have been provided for the Corporation the balance if any due to them in their collection accounts after the amounts due from the said accounts to the Corporation in respect of the payment made or provided for by the Corporation have first been paid in accordance with the provisions of sub-clause (a) above ;

Provided that the amount due to the Corporation shall, if it becomes necessary so to do, be provided for in the books of the transferee bank and be paid to the Corporation in the manner specified in clause (b) of regulation 22 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961

Provided further that the transferee bank shall make the payments referred to in clause (b) above.

(i) if the corresponding or similar account mentioned in clause (b) of paragraph (5) has not been closed or has not matured for payment, by credit to that account, and

(ii) if the said account has been closed or has matured for payment, in cash ;

(vi) The amounts due to the Corporation in terms of sub-clause (a) of clause (v) above and the amounts due to the collection accounts of the depositors in terms of sub-clause (b) of that clause shall rank equally among themselves, and if they cannot be paid in full shall abate in equal proportions ;

(vii) After the payments referred to in clause (v) of this paragraph have been made or provided for in full, the transferee bank shall, out of the balance of the amounts referred to in clause (v) which may be available to it make payments pro rata towards the amounts, if any, due to the accounts of the former shareholders of the transferor bank in the manner and to the extent specified below :

(a) in the first place, the amounts, if any, due to the accounts of the former preference shareholders of the transferor bank till payment in full against all the accounts has been made ;

(b) in the second place, the amounts, if any, due to the accounts of the former ordinary shareholders of the transferor bank till payment in full against all the accounts has been made ; and thereafter

(c) in the third place, the amounts, if any, due to the accounts of the former deferred shareholders of the transferor bank till payment in full against all the accounts has been made ;

- (d) after all the amounts mentioned in sub-clause (a), (b) and (c) above have been paid in full, the surplus, if any, remaining in the hands of the transferee bank shall be distributed pro rata among the former ordinary shareholders of the transferor bank.

Provided that if any question arises whether any amounts are due against an account mentioned in any of the above sub-clauses, it shall be referred to the Reserve Bank of India whose decision thereon shall be final.

(viii) the amounts due to the collection accounts referred to in this paragraph shall be deemed to be a liability of the transferee bank only to the extent provided for in this scheme;

(ix) on the expiry of twelve years from the prescribed date or such earlier period as the Central Government after consulting the Reserve Bank of India may specify for this purpose, any item referred to in clause (ii) of this paragraph which may not have been realised by that date shall be valued by the transferee bank in consultation with the Reserve Bank of India and the transferee bank shall distribute any amount or amounts determined in the light of that valuation after deducting therefrom first any sum necessary for meeting the liabilities referred to in clause (iv) of this paragraph which may remain unsatisfied as on that date in the order and the manner provided in clauses (v), (vi) and (vii) above.

(x) The transferee bank shall invest such moneys realised on account of items mentioned in the preceding clauses (i), (ii) and (iii) as are not likely to be required by it for immediate payment, in interest bearing deposits with itself or with any other bank or banks, in such manner and for such periods as may be appropriate having regard to the facts and circumstances of the case or as the Reserve Bank of India may direct. The interest accrued shall be applied for meeting the liabilities referred to in clauses (iv), (v), (vi) and (vii) in the manner indicated therein.

(7) Notwithstanding anything to the contrary contained in any contract, express or implied, interest shall be paid in respect of the new accounts opened with the transferee bank in terms of paragraph (5) and credited in accordance with the provisions of that or the next succeeding paragraphs and at such rates as the transferee bank may allow.

(8) No depositor or other creditor of the transferor bank shall be entitled to make any demand against the transferor bank or the transferee bank in respect of any liability of the transferor bank to him except to the extent prescribed by this scheme.

(9) No suit or other legal proceedings shall lie against the Central Government, the Reserve Bank of India or the transferee or the transferor bank for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this scheme.

(10) All the employees of the transferor bank shall continue in service and be deemed to have been appointed by the transferee bank at the same remuneration and on the same terms and conditions of service as were applicable to such employees immediately before the close of business on 10th June, 1989 :

Provided that the employees of the transferor bank who have, by notice in writing given to the transferor or the transferee bank at any time before the expiry of one month next following the date on which this scheme has been sanctioned by the Central Government intimated their intention of not becoming employees of the transferee bank, shall be entitled to the payment of such compensation, if any, under the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 and such pension, gratuity, provided fund and other retirement benefits as may be ordinarily admissible under the rules of authorisations of the transferor bank immediately before the close of business on 10th June, 1989

Provided further that the transferee bank shall in respect of the employees of the transferor bank who are deemed to have been appointed as employees of the transferee bank be deemed also to have taken over the liability for them of retrenchment compensation in the event of their being retrenched while in the service of the transferee bank on the basis that their service has been continuous and has not been interrupted by their transfer to the transferee bank.

(11) The transferee bank shall, on the expiry of a period not longer than three years from the date on which this scheme is sanctioned, pay or grant to the employees of the transferor bank the same remuneration and the same terms and conditions of service as are applicable to the employees of corresponding rank or status of the transferee bank subject to the qualifications and experience of the said employees of the transferor bank being the same as or equivalent to those of such other employees of the transferee bank.

Provided that if any doubt or difference arises as to whether the qualifications or experience of any of the said employees are the same as or equivalent to the qualifications and experience of the other employees of corresponding rank or status of the transferee bank or as to the procedure of principles to be adopted for the fixation of the pay of the employees in the scales of pay of the transferee bank, the doubt or difference shall be referred to the Reserve Bank of India whose decision thereon shall be final.

(12) The trustees or administrators of any provident fund and/or gratuity fund constituted for the employees of the transferor bank or as the case may be the transferor bank shall on or as soon as possible after the prescribed date transfer to the trustee of the employees provident fund and/or gratuity fund constituted for the transferee bank, or otherwise as the transferee bank may direct, all the monies and investments held in trust for the benefit of the employees of the transferor bank :

Provided that such latter trustees shall not be liable for any deficiency in the value of investments, or in respect of any act, neglect, or default done before the prescribed date.

(13) The transferee bank shall submit to the Reserve Bank of India such statements and information as may be required by the Reserve Bank of India from time to time regarding the implementation of this scheme.

(14) The transferee bank shall furnish to the shareholders of the transferor bank a statement of affairs of the transferor bank in such form and at such periodical intervals as the Reserve Bank of India may specify in this behalf. The sending of such statements shall be discontinued when so directed by the Reserve Bank.

(15) Any notice or other communication required to be given by the transferee bank shall be considered to be duly given if addressed and sent by pre-paid ordinary post to the addressee at the address registered in the books of the transferor bank, until a new address is registered in the books of the transferee bank, and such notice shall be deemed to be served on the expiry of forty eight hours after it has been posted. Any notice or communication which is of general interest shall be advertised in addition in one or more daily newspapers which may be in circulation at the places where the transferor bank was transacting its business.

(16) If any doubt arises in interpreting any of the provisions of this scheme, the matter shall be referred to the Reserve Bank of India and its opinion shall be conclusive and binding on both the transferee and transferor banks, and also on all the members, depositors and other creditors and employees of each of these banks and on any other person having any rights or liability in relation to any of these banks

(17) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this scheme, the Central Government may issue to the transferor and the transferee banks or to either of them such directions not inconsistent with this scheme as may appear to the Central Government, after consulting the Reserve Bank of India, to be necessary or appropriate for the purpose of removing the difficulty.

ने उसके द्वारा जारी किया गया स्थगनादेश दिनांक 6 अक्टूबर, 1989 तक और इसके सहित लागू रहेगा।

[संख्या 17/2/89-डी ओ.-III(iii)]

मन्त्रेश्वर झा, नयुक्त सचिव

[No. 17/2/89-B.O. III(ii)]

का.आ. 880(अ)--बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक 10 जून, 1989 की अधिसूचना संख्या का.आ. 434(अ) के द्वारा यथासंशोधित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक 6 अक्टूबर, 1989 की अधिसूचना संख्या का.आ. 793(अ) में संशोधन करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, निर्देश देती है कि यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि., कलकत्ता के संयंत्र

S.O. 880(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), and in modification of the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs No. S.O. 434(E) dated the 10th June, 1989, as modified by the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs No. S.O. 793(E) dated the 6th October, 1989, the Central Government, hereby directs that the order of moratorium made by it in respect of the United Industrial Bank Limited, Calcutta, shall remain in force upto and inclusive of the 30th October, 1989.

[No. 17/2/89-B.O. III(iii)]

MANTRESHWAR JHA, Jt. Secy.

